Hindustan-New Delhi-04-03-2011

# खुलने वाले हैं 20 ट्रिपल आईटी

## केंद्र, राज्यों एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी क्रमश : 50, 35 और 15 फीसदी होगी

मदन जैड़ा

नई दिल्ली

देश में निजी क्षेत्र की मदद से 20 भारतीय सूचना प्रद्यौगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों एवं निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित करने का फैसला किया है। इसके लिए छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है जिसका चेयरमैन इंफोसिस निदेशक टीवी मोहनदास पाई को नियुक्त किया है। समिति दो माह में तय करेगी कि ट्रिपल आईटी कहां खुलेंगे और किसी कंपनी के साथ साझीदारी में खोले जाएंगे।

देश में अभी चार ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ग्लालियर, जबलपुर तथा

कांचीपुरम में हैं जो पूरी तरह से केंद्र वित्त पोषित हैं। लेकिन नए खुलने वाले 20 ट्रिपल आईटी में केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्र की भागीदारी होनी है।

इनमें केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 50, 35 और 15 फीसदी की होगी। इसके अलावा जो राज्य अपने यहां ट्रिपल आईटी खोलना चाहेंगे उन्हें 50 एकड़ जमीन भी निशुल्क देनी होगी। केंद्र सरकार एक आईटी की स्थापना के लिए 128 करोड़

### निजी भागीदारी

- इंफोसिस निदेशक के नेतृत्व में छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित
- छह महीने में देगी रिपोर्ट, कमेटी तय करेगी किस राज्य में खोला जाए

और फैकल्टी विकास के 50 करोड़ रुपये देगी। कैबिनेट इसके लिए 2808 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुकी है।

पाई की अध्यक्षता वाली कमेटी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद के निदेशक राजीव संगल, ट्रिपल आईटी ग्वालियर के निदेशक एसजी देशमुख, आईटी महकमे के संयुक्त सचिव एन. रविशंकर, दिल्ली के प्रधान सचिव आनंद प्रकाश हैं। समिति आईटी की स्थापना के लिए नियम कायदे तय करेगी। जिन राज्यों में ट्रिपल आईटी नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता देने की बात कही गई है।